एक दशक की बैलेंस शीट!

खाद्य सुरक्षा एवं पोषण

रिपोर्ट कार्ड 2014-24

लोकतंत्र का सार यह है कि हम सरकारों को उनके दावों और वादों के हिसाब से जवाबदेह बनाएं। लेकिन हाल के वर्षों की सबसे बड़ी क्षति जवाबदेही का विचार रही है। मीडिया में विभाजनकारी और अंधराष्ट्रवादी अतिशयोक्ति सामूहिक भूलने की बीमारी को बढ़ावा देती है। यह रिपोर्ट कार्ड (हालांकि निर्णायक नहीं) वित्तीय जवाबदेही नेटवर्क इंडिया की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो वित्तीय और आर्थिक दृष्टिकोण से विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के प्रदर्शन के कुछ दावों और वास्तविकता पर नज़र डालने और उजागर करने का प्रयास करता है।

फाइनेंशियल एकाउंटेबिलिटी नेटवर्क इंडिया - फैन इंडिया

दावा

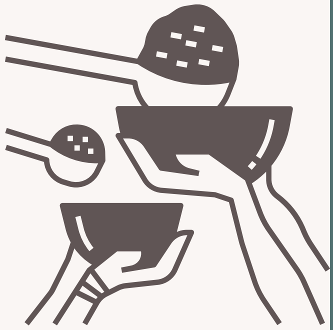

1. **बीजेपी घोषणापत्र 2014:** "अनियंत्रित खाद्य महंगाई ने घरेलू बजट को खराब कर दिया है और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की निगरानी में समग्र मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में योगदान दिया है। इससे भी बुरी बात यह है कि लाखों लोगों की भोजन और पोषण सुरक्षा खतरे में है। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का कीमतें थामने का रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरों के दुष्चक्र को तोड़ने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है।''

2. भाजपा ने हमेशा माना है कि **'सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा'** राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग है। भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि इसकी पहुंच आम आदमी तक हो और भोजन का अधिकार सिर्फ कागजी कार्रवाई या राजनीतिक बयानबाजी बनकर न रह जाए।

3. **भाजपा घोषणापत्र 2014:** "बच्चों के कल्याण से संबंधित संकेतक राष्ट्र की प्रगति के संकेतक हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा या बच्चों की सुरक्षा हो। यूपीए शासन के तहत, इसे उचित महत्व नहीं दिया गया है। भाजपा कुपोषण और अल्पपोषण जैसे बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।''

4. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने दावा किया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन से भोजन की चिंता खत्म हो गई है

5. "मुझे पूरा विश्वास है कि अमृत काल में, आप जैसे देश के करोड़ों लोगों का, आकांक्षाओं से भरा हुआ उत्साह, भव्य और विकसित भारत के निर्माण के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा" - उज्ज्वला पर पीएम मोदी

हकीक़त

- लगातार खाद्य असुरक्षा के बावजूद, वित्त वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्य सब्सिडी के लिए वित्त वर्ष 24 के लिए 2.12 लाख करोड़ के [आवंटित बजट]() रुपये के संशोधित अनुमान से **घटकर** 2.05 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह 3.33% की कमी है।

- खाद्य सब्सिडी के लिए आवंटित कुल बजट का हिस्सा लगातार कम हुआ है, वित्त वर्ष 2015 में 6.4% से **घटकर** वित्त वर्ष 2025 में 4.3% हो गया है। वित्त वर्ष 23 के बाद से, आवंटन पूर्व-कोविड समय की तुलना में काफी कम रहा है।

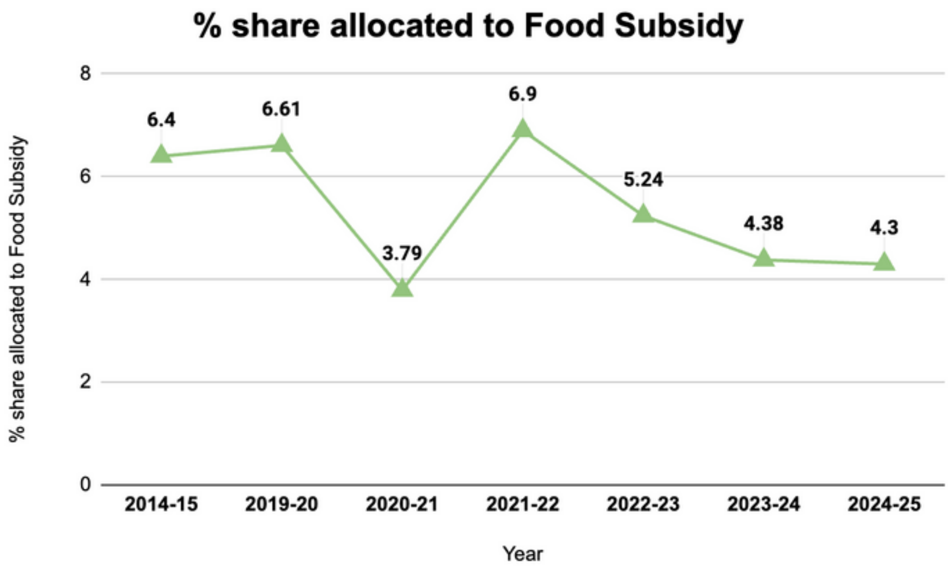

ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत वर्तमान में 125 देशों में से 111वें स्थान पर है

वर्ष	रैंक
2018	103
2019	102
2020	94
2021	101
2022	107
2023	111

- 80 करोड़ से अधिक परिवार अभी भी COVID-19 के बाद से उबर रहे हैं, **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) जो अप्रैल 2020 में शुरू** की गई थी, **दिसंबर 2022 में बंद** कर दी गई थी। इसका उद्देश्य एनएफएसए कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज राशन प्रदान करना था। हर महीने मुफ़्त इस पात्रता को बंद करने से **परिवारों पर खाद्य पदार्थों की खरीद पर अतिरिक्त आय खर्च करने का दबाव** पड़ेगा।

- उज्ज्वला योजना पूरी तरह विफल रही है. बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की बढ़ती लागत के बावजूद, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 2014 के बाद से **2.5 गुना** बढ़ गए हैं। आम चुनावों से पहले, अगस्त 2023 में इन कीमतों में **200 रुपये** और मार्च 2024 में 100 रुपये की कटौती की गई थी।

- उज्जवला योजना के तहत पंजीकृत **90 मिलियन 'लाभार्थियों'** में डेटा से पता चलता है की है कि लोगों ने या तो रिफिलिंग नहीं करवाया है या केवल एक बार रिफिलिंग करवाया है।

Financial Year	Number of Customers taken no refill under PMUY (in Crore)	Number of Customers taken only one refill (including installation refill) (in crore) under PMUY
2017-18	0.46	1.19
2018-19	1.24	2.90
2019-20	1.41	1.83
2020-21	0.10	0.67
2021-22	0.92	1.08

Source:- Indian Oil Corporation Limited (IOCL) on behalf of all Oil Marketing Companies.

- नवीनतम नेशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे से पता चलता है कि भारत में पाँच वर्ष से कम उम्र के **36% बच्चे अविकसित** (या अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे) हैं। रिपोर्ट स्वयं कहती है कि यह **"दीर्घकालिक अल्पपोषण का संकेत"** है। **पांच साल से कम उम्र के 32% बच्चे कम वजन** के हैं।

- रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 6-23 महीने की उम्र के सभी बच्चों में से केवल **11% को स्वीकृत आहार शिशु और छोटे बाल आहार के अनुसार न्यूनतम स्वीकार्य आहार** दिया गया था।

- 2018 में शुरू की गई एनीमिया मुक्त भारत जैसी पहल के बावजूद, राष्ट्रीय और परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 से पता चलता है कि **15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया 2015-16 में 53% से बढ़कर 2019-20 में 57.2%** हो गया है। **15 से 49 वर्ष की गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 50.4% से बढ़कर 52.2%** हो गई है।

- **67% बच्चों में कुछ हद तक एनीमिया था**
(अर्थात्, उनका हीमोग्लोबिन स्तर 11.0 जी/डीअल से कम है)
- मोदी के वर्षों में, 2015-16 और 2019-21 के बीच, 6-59 महीने की उम्र के बच्चों में एनीमिया की व्यापकता **59% से बढ़कर 67%** हो गई और ग्रामीण बच्चों में यह अधिक बनी रही।
- "विकास मॉडल" के दिखावे को उजागर करते हुए **6-59 महीने की उम्र के बच्चों में एनीमिया की व्यापकता गुजरात के बच्चों में सबसे अधिक (80%) है!**

Image Credits: UNICEF

- नवीनतम ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, भारत में वेस्टिंग दर सबसे अधिक है और पांच वर्ष से **कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग के मामले में भारत विश्व स्तर पर पांचवें स्थान पर** है।

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 को देखते हुए, अर्थशास्त्री दीपा सिन्हा बताती हैं कि जहां **एससी और एसटी के बीच स्टंटिंग की व्यापकता लगभग 40 प्रतिशत है, वहीं "अन्य" समूह के बच्चों में यह 30 प्रतिशत** है, जो मुख्य रूप से है। इसमें ऊंची जाति के हिंदू शामिल हैं।

- वह यह भी दिखाती है कि कैसे **शहरी क्षेत्रों (30%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों (37%) में बौनापन बहुत अधिक है और बिहार (43%) में इसका प्रसार केरल (23%) से लगभग दोगुना** है।

- अगर हम बौनेपन के शिकार वाले बच्चों की आबादी को देखें तो **शीर्ष संपत्ति वर्ग में 23% बच्चे बौनेपन के शिकार हैं, जबकि निचले स्तर पर 46% बच्चे** हैं।

Image Credits: Kunal Patil/Hindustan Times via Getty Images

- वर्ल्डबैंक के आंकड़ों केअनुसार बांग्लादेश, घाना और वियतनाम जैसे देशों में औसत रेटिंग दर क्रमशः **28%, 18% और 20%** है, जो कि भारत के सबसे अच्छे तुलनीय देशों में से भी कम है।

- फरवरी 2024 में जामा नेटवर्क ओपन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि **6-23 महीने की उम्र के उन बच्चों की संख्या में भारत तीसरे स्थान पर है, जिन्होंने पिछले 24 घंटों में कोई खाना नहीं खाया था**।

- अध्ययन में भारत में लगभग **67 लाख बच्चों की पहचान की गई जो 'शून्य-भोजन' श्रेणी** में आते हैं।

- **मध्याह्न भोजन योजना (पीएम पोषण) के लिए आवंटन वित्त वर्ष 2014 में 0.79% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 0.23% हो गया।**

- भोजन के भगवाकरण के कारण कई राज्यों में **बच्चे मध्याह्न भोजन में अंडे से वंचित** हो गए हैं। **अंडे आवश्यक पोषण संबंधी पूरक प्रदान करते हैं जो बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और अल्पपोषण के मुद्दों से निपटने में मदद कर सकते हैं।**

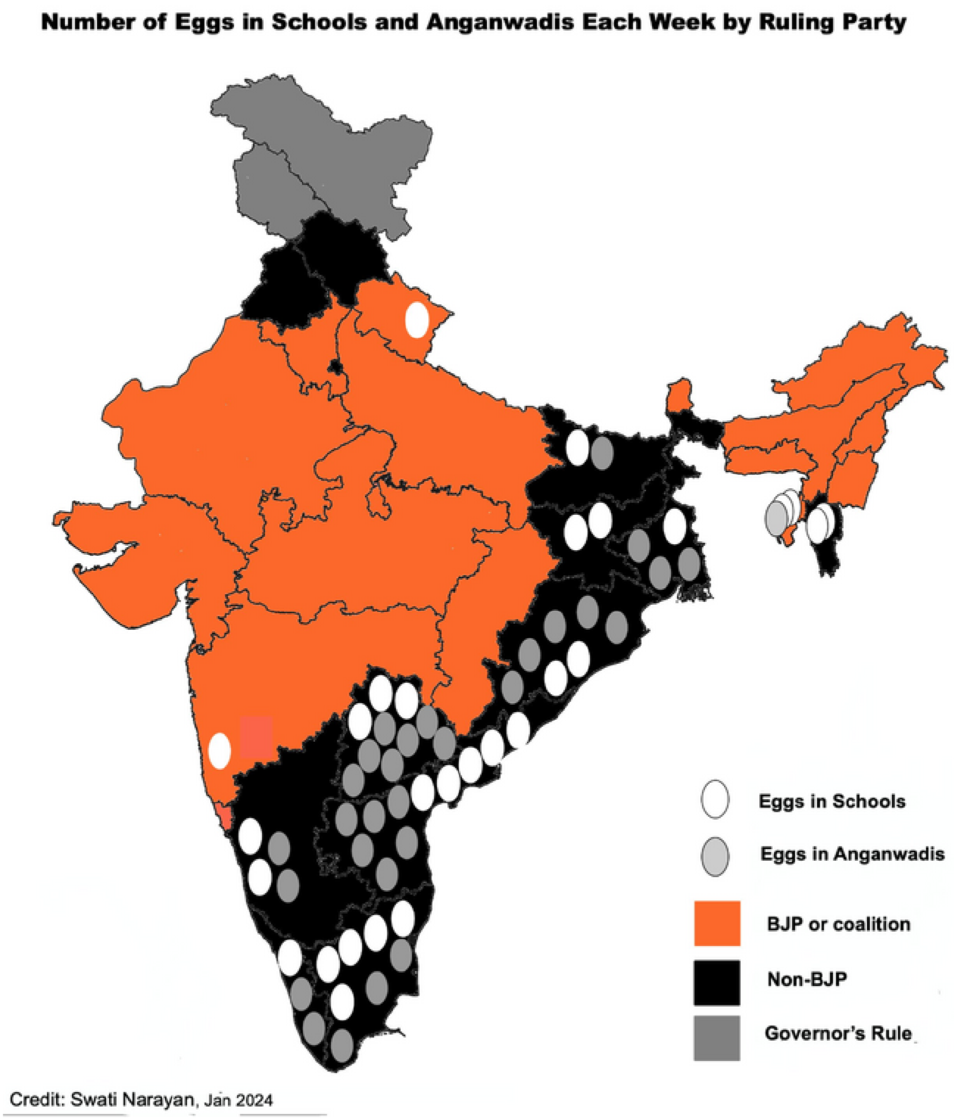

हाइलाइट्स

1. जनगणना के संचालन में देरी के कारण करोड़ों लोग अपने उचित अधिकारों तक पहुंचने से वंचित रह गए हैं। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि एनएफएसए के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न के हकदार लोगों की संख्या लगभग 100 करोड़ है।

2. 5 वर्ष से कम उम्र के **बच्चों में वेस्टिंग दर 18.2% है और स्टंटिंग दर 35.5%** है। एनएफएचएस 4 और एनएफएचएस 5 के बीच, **21 राज्यों में बच्चों में स्टंटिंग में वृद्धि** हुई है।

3. एक आरटीआई जवाब से पता चला कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या **2019-20 में 96 लाख से घटकर 2021-22 में 61 लाख** हो गई। वर्तमान में, इस योजना के तहत **महिलाओं को एनएफएसए के तहत अनिवार्य 6,000 रुपये की तुलना में केवल 5,000 रुपये** मिलते हैं।

4. **संसद के एक जवाब** के मुताबिक, देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में 12,93,448 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 11,64,178 आंगनवाड़ी सहायिकाएं काम कर रही हैं। इनमें से **देशभर में 70,444 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताके पद और 1,23,287 आंगनवाड़ी हेल्पर के पद खाली** हैं।

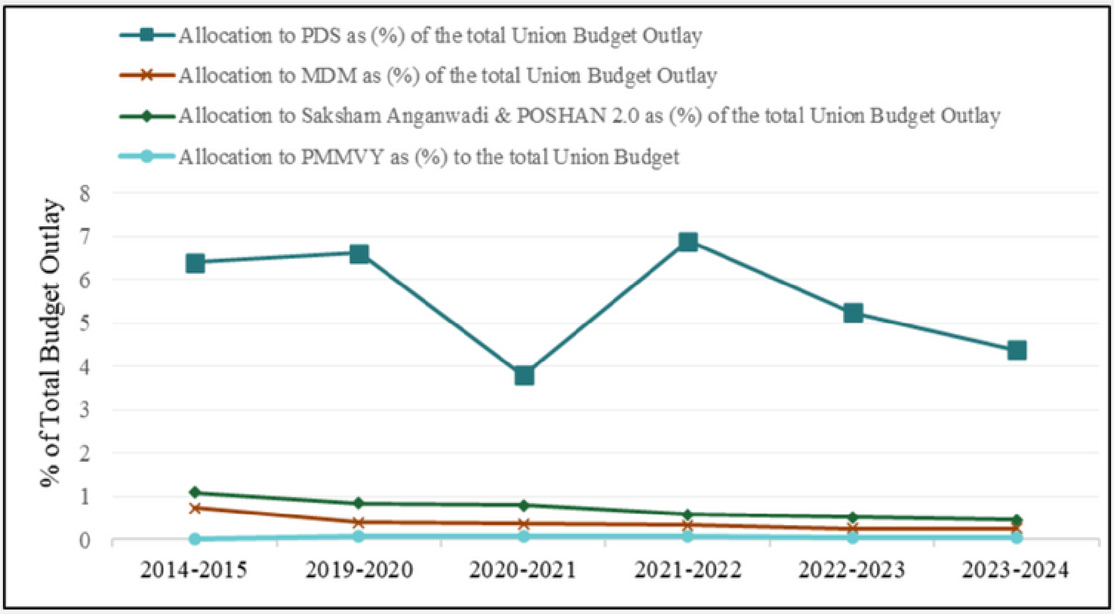

(%) Share of allocation of the total budget outlay for PDS/MDM/Saksham Anganwadi & POSHAN 2.0/ & PMVVY (Budget Estimate)

Image Credits: Sneha Richhariya via Maktoob Media

अन्य रिपोर्ट कार्ड के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ऊपर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें:

https://bit.ly/BSofadecade

https://www.fanindia.net Financial Accountability Network

@_FANIndia Financial Accountability Network India - FAN India fanindia.info@gmail.com

FINANCIAL ACCOUNTABILITY NETWORK INDIA